

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 31 अगस्त, 2007

विषय: जनपद देहरादून में कार्लीगाड़ पेयजल योजना के अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1626/मुअवि/बजट/बी-1 योजना दि० 10.5.07 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "जनपद देहरादून के आपेक्षाकृत ऊंचाई वाले क्षेत्रों की पेयजल समस्या के निदान हेतु सहस्त्रधारा में अपस्ट्रीम पर कार्लीगाड़ पेयजल योजना के अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य की योजना" लागत रु० 39.80 लाख टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रु० 30.25 लाख (रुपये तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- 2- उक्त कार्यों के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय।
- 3- स्वीकृत की जा रही योजनाओं का कार्य दिनांक-31.03.08 तक पूर्ण किया जाय और पूर्ण करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र वित्त आयोग निदेशालय तथा शासन को प्रतिमाह अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- आगणनों में उल्लिखित दरों का दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कराया जाय। जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त की जाय।
- 6- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- 7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- 8- एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- 9- कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भान्ति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 12- धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष-2007-08 की अनुदान सं०-20 के लेखाशीर्षक 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-समान्य आयोजनागत 005-सर्वेक्षण तथा अनुसंधान, 03-निर्माण कार्य, 42-अन्य व्यय के नाम में डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-291/XXVII (2)/2007 दि० 13.8.07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 3638 / 11-2007-04(06)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून ।
7. गार्ड फाईल ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव